उत्तराखण्ड के कुमाऊँ व गढ़वाल मण्ड़ल में परिवार सहित एवं एकल पलायन करने वाले निवासियों के मध्य सामाजिक स्तर पर पलायन के प्रभाव का अध्ययन

प्राप्तिः12.12.25
स्वीकृतः 22-12-25

102

डॉ. पुष्पा पोखरिया
वाणिज्य विभाग
पंडित बद्री दत्त पांडेय परिसर, बागेश्वर
ईमेलः poojapokhariya95@gmail.com

डॉ. सी. एस. जोशी
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
वाणिज्य विभाग
एम. बी. राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, हल्द्वानी

साराशं

यह अध्ययन उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डलों में परिवार सहित तथा एकल पलायन करने वाले निवासियों के मध्य सामाजिक स्तर पर पलायन के प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन हेतु 580 उत्तरदाताओं से प्राथमिक आँकड़े प्रश्नावली के माध्यम से संकलित किए गए। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्रतिशत, औसत तथा एनोवा का प्रयोग किया गयज्ञं अध्ययन से ज्ञात हुआ कि पलायन के पश्चात् दोनों प्रकार के पलायनकर्ताओं (परिवार सहित एवं एकल) में सामाजिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुए। रहन सहन स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवहन सुविधा तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं वन्य जीवों से सुरक्षा के संदर्भ में औसतन लगभग 67.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक प्रभाव व्यक्त किया। एनोवा परीक्षण में p-value(0.868884) 0.05 से अधिक पाई गई, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिवार सहित एवं एकल पलायनकर्ताओं के मध्य सामाजिक प्रभाव में सांख्यिकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। अतः यह अध्ययन दर्शाता है कि उत्तराखण्ड में पलायन सामाजिक स्तर पर सुधार की दृष्टि से प्रेरित है तथा इसके प्रभाव दोनों समूहों में लगभग समान हैं।

मुख्य शब्द

पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तराखंड, कुमाऊ, गढ़वाल।

प्रस्तावना

उत्तराखंड के कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, परिवहन व्यवस्था की सीमित उपलब्धता तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं वन्यजीवों के बढ़ते संकट जैसी परिस्थितियाँ लोगों को अपने मूल निवास स्थान को छोड़ने के लिए विवश करती हैं। इन समस्याओं के कारण ग्रामीण जनसंख्या को आजीविका, शिक्षा और बेहतर जीवन–स्तर की खोज में अन्य स्थानों की ओर रुख करना पड़ता

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.102

है। परिणामस्वरूप राज्य में ग्रामीण से शहरी अथवा अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों की ओर निरंतर पलायन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिससे ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक संरचना प्रभावित हो रही है।

राज्य में पलायन मुख्यतः दो रूपों में परिलक्षित होता है। पहला, परिवार सहित पलायन, जिसमें संपूर्ण परिवार स्थायी या अर्ध–स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर निवास करने लगता है। दूसरा, एकल पलायन, जिसमें परिवार का केवल एक सदस्य अधिकतर पुरुष या युवा वर्ग रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य से बाहर जाकर निवास करता है, जबकि शेष परिवार मूल स्थान पर ही रहता है। दोनों ही प्रकार के पलायन के अपने–अपने सामाजिक एवं आर्थिक निहितार्थ होते हैं।

यद्यपि पलायन को सामान्यतः आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, किंतु इसका प्रभाव केवल आय या रोजगार तक सीमित नहीं रहता। पलायन व्यक्ति एवं परिवार के सामाजिक स्तर को भी व्यापक रूप से प्रभावित करता है। रहन–सहन की गुणवत्ता, सामाजिक प्रतिष्ठा, जीवन–शैली, आवगमन सुविधा, सुरक्षा की भावना तथा आत्म–संतुष्टि जैसे सामाजिक आयामों में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो पलायन के सामाजिक प्रभावों को रेखांकित करते हैं।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखंड राज्य के कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डलों में परिवार सहित तथा एकल पलायन करने वाले निवासियों के सामाजिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि क्या दोनों प्रकार के पलायनकर्ताओं के सामाजिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों में कोई महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है या फिर दोनों पर इसका प्रभाव लगभग समान है।

इस प्रकार, यह शोध उत्तराखंड में पलायन की सामाजिक संरचना को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो राज्य में ग्रामीण विकास नीतियों के निर्माण तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर सकता है।

साहित्य की समीक्षा

डॉ चौधरी सयंतनी रॉय और सुश्री जोर्डर सुरंजना (2020) प्रवासियों की बदकिस्मती और घर लौटने का उनका संघर्ष कई दिनों से मीडिया का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। दर्दनाक अनुभव के कारण प्रवासी भविष्य में शहरों में वापस नहीं आना चाहते हैं। वे अब अपनी जमीन पर लौटने के लिए उत्सुक हैं और वहां कम से कम कमाए जा सकने वाले न्यूनतम पर टिके रहते हैं। एनएसएसओ और जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी शहरों में महत्वपूर्ण प्रवासन हुआ है; इनमें से अधिकांश अंतर्राज्यीय ग्रामीण शहरी प्रवास प्रति के हैं। लेकिन जनगणना के आंकड़े अल्पकालिक सर्कुलर प्रवासियों पर विचार नहीं करते हैं, जो कुल प्रवासी कार्यबल का एक बड़ा प्रतिशत है। 2007 08 में एनएसएसओ द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 1.258 मिलियन अल्पावधि प्रवासी श्रमिक निवास कर रहे थे।

डोलिंस्का ए, जोल्ज़ी आर, पॉस्कर्ट रोकिता डी. (2020) उद्देश्यः इस लेख का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवा आंतरिक प्रवास, जैसा कि आम तौर पर स्वीकार किया जाता है, अस्थायी नहीं है, लेकिन अंतिम इरादे में स्थायी है। डिजाइन/पद्धति/दृष्टिकोणः सर्वेक्षण दो अलग अलग क्षेत्रों में किया गयाः एक मजबूत (बड़े) क्षेत्रीय केंद्र के साथ और दूसरा कमजोर (छोटे) केंद्र के साथ। उन क्षेत्रों में विभिन्न आकार के माध्यमिक शिक्षा केंद्रों का चयन किया

गया था। सामान्य माध्यमिक विद्यालयों से स्नातक होने वाले 2380 युवाओं के बीच एक सभागार सर्वेक्षण किया गया था। अध्ययन का आधार एक सर्वेक्षण था जिसमें कई प्रश्न थे और पृष्ठभूमि कानूनी डेटा से संबंधित पांच विशेषताओं का निर्धारण किया गया था। निष्कर्षः शिक्षा का पलायन "अध्ययन के लिए" एक बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में महानगरीय शहर को संबोधित अंतिम प्रवास की शुरुआत बन जाता है। शोध के परिणामों ने यह भी साबित किया कि बड़े क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा छोटे क्षेत्रों के केंद्रों को निकालने की प्रक्रिया से क्षेत्रों, विशेष रूप से उनकी राजधानियों के विकास में अंतर गहराता है। व्यावहारिक निहितार्थः विश्लेषण के परिणामों का उपयोग एक उपयुक्त विकास नीति को आकार देने में किया जा सकता है। वे देश के क्षेत्रीय विभाजन की वास्तविक प्रक्रियाओं के लिए छोटी क्षेत्रीय राजधानियों या एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए आनुपातिक समर्थन से अधिक की आवश्यकता का संकेत दे सकते हैं। मौलिकता/मूल्यः शोध के परिणाम प्रवास और स्थानीय और क्षेत्रीय विकास के संबंध में सैद्धांतिक मॉडल के निर्माण में योगदान कर सकते हैं।

अली बसरत एम डी (2020) रेडी मेड गारमेंट उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का दिल है। उद्योग लगभग 4.2 मिलियन लोगों को रोजगार दे रहा है, जो औद्योगिक रोजगार में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में श्रमिकों का पलायन एक सामान्य घटना है। बार बार श्रम प्रवास कुल परिधान उत्पादन को प्रभावित करता है और कम करता है गुणवत्ता सहित उत्पादन। इस श्रम प्रवास के पीछे कुछ कारण हैं जैसे अच्छे काम के माहौल का ताला, उचित सुरक्षा और आराम, उच्च मजदूरी, उपलब्ध वाष्पोत्सर्जन, आवास सुविधा आदि। इस शोध का मुख्य फोकस श्रमिक प्रवास पर सुरक्षा और आराम के प्रभाव की पहचान करना था। ऐसा करने के लिए कुछ विशेषज्ञों और माननीय थीसिस पर्यवेक्षक की मदद से सुरक्षा के लिए 09 (नौ) प्रश्न और आराम के लिए 13 (तेरह) प्रश्नों से युक्त एक अर्ध संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। फिर विभिन्न 05 (पांच) परिधान कारखानों से 250 हितधारकों (प्रत्येक कारखाने से 50) पर एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में अधिकांश भाग लेने वाले श्रमिक थे लेकिन प्रशासनिक कर्मी भी शामिल थे। कुल सर्वेक्षण शोधकर्ता द्वारा सीधे साक्षात्कार का उपयोग करके किया गया था। इस शोध से यह पाया गया कि यदि श्रमिकों को सम्मानजनक कार्य वातावरण के साथ साथ उचित सुरक्षा और आराम मिले तो श्रम प्रवास को कम किया जा सकता है।

डॉ. नेट्टीकलप्पा कुम्मारा, डॉ. नाइक.के.कृष्णा (2020) लोगों का प्रवासन दुनिया भर में एक स्वीत घटना है जहां लोग भोजन, काम, सुरक्षा और आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय जैसे अनुसूचित जनजाति बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करते हैं। आदिवासी महिलाएं जिन्हें "संपत्ति" के रूप में जाना जाता है, झारखंड के आदिवासी समुदायों से पिछले कुछ दशकों से अकेले या समूहों में संबंधपरक आजीविका उद्देश्यों के लिए बड़ी संख्या में हैं। एक महिला को अपने परिवार का केंद्रक कहा जाता है और मानव समाज का आधा हिस्सा होता है जिसके बिना एक समाज अधूरा है और पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए इंसान हैं यानी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। फिर भी यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर जगह महिला अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं के साथ भेदभाव और दमन किया जा रहा है और लाखों महिलाएं यौन और शारीरिक उत्पीड़न, दहेज हत्या और यातना, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, भ्रूण हत्या जैसी अनकही हिंसा और दुर्व्यवहार झेलती हैं। शिशुहत्या आदि और यह जारी है। वर्तमान अध्ययन आंध्र प्रदेश के अनंत पुरमू जिले में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर प्रवास के प्रभाव पर केंद्रित है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.102

Joshi & Jindal (2022) ने ग्रामीण सहकारी क्षेत्रीय बैंकों की सेवा गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता आजीविका सृजन और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कमजोर बैंकिंग सेवाएँ ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के लिए प्रेरित करती हैं। Jindal (2021) ने उत्तराखंड के सहकारी बैंकों की सेवाओं का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला कि सीमित ऋण सुविधा और तकनीकी पिछड़ापन ग्रामीण विकास में बाधक हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से पलायन को बढ़ावा देते हैं। Jindal & Srivastava (2021) तथा Jindal (2020) ने सहकारी बैंकों में ग्राहक संतुष्टि का अध्ययन किया और पाया कि सेवा गुणवत्ता, विश्वास तथा पहुँच ग्रामीण लोगों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सेवा असंतोष ग्रामीण–शहरी असंतुलन को जन्म देता है। Saxena & Jindal (2019, 2021) के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी बैंकों की सेवा गुणवत्ता में अंतर सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों की ओर झुकाव बढ़ता है। Jindal & Jindal (2020) ने कोविड–19 काल में ऑनलाइन बैंकिंग की उपयोगिता का अध्ययन कर बताया कि डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी रही, जिससे ग्रामीण लोग बेहतर सेवाओं के लिए पलायन करने को प्रेरित हुए।

Goswami & Jindal (2021)ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रति किसानों की जागरूकता का अध्ययन करते हुए पाया कि ऋण सुविधाओं पहुँच कृषि को अलाभकारी बनाती है। यह स्थिति ग्रामीण युवाओं को गैर–कृषि रोजगार हेतु शहरों की ओर पलायन के लिए प्रेरित करती है। Arya Jindal (2020) ने मानव पलायन, डिजिटल बाजार और बैंकिंग सेवाओं के अंतर्संबंध का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि उत्तराखंड में पलायन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक – संरचनात्मक समस्या भी है। Singh & Jindal (2025) ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन कर बताया कि गाँवों से जनसंख्या के पलायन से पारंपरिक संस्कृति, सामुदायिक जीवन और सामाजिक पूँजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। Sharma & Jindal (2022) तथा Sharma, Jindal & Bajpai (2022) ने उत्तराखंड के सहकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण किया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि वित्तीय संस्थानों की कमजोर स्थिति ग्रामीण निवेश और रोजगार सृजन को सीमित करती है, जो पलायन को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती है।

उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डलों में परिवार सहित एवं एकल पलायन करने वाले निवासियों के मध्य सामाजिक स्तर (रहन सहन, सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा एवं परिवहन सुविधा आदि) पर पलायन के प्रभाव का तुलनात्मक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण करना।

परिकल्पना

परिवार सहित एवं एकल पलायन करने वाले निवासियों के सामाजिक स्तर के औसत प्रभाव में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस शोध पत्र में वर्णनात्मक तथा संख्यात्मक विधि का प्रयोग किया गया है अध्ययन के उददेश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिक आकड़ो का प्रयोग किया गया है तथा प्राथमिक आंकड़े

राज्य के सभी जिलों से पलायन कर चुके लोगों से एकत्रित किये गए हैं तथा एकत्रित आकड़ों का विश्लेषण करके परिणाम ज्ञात किया गया है।

इस अध्ययन में समस्त उत्तराखण्ड़ राज्य के कुमाऊँ व गढ़वाल मण्ड़ल के समस्त 13 जिलों को सम्मिलित किया गया है जिसमें से कुमाऊं मण्ड़ल से 6 जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर व चम्पावत हैं तथा गढ़वाल मण्ड़ल से 7 जिले चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौढ़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग जिला लिए गए हैं तथा प्रतिदर्श का संकलन प्रश्नावली के माध्यम से उत्तराखण्ड़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से राज्य के भीतर पलायन करने वाले 580 पलायनकर्ताओं से आंकड़ों का संकलन किया गया है।

इस अध्ययन में विभिन्न सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग किया गया है जिसमें प्रतिशत, औसत, व एनोवा विधि का उपयोग किया गया है।

तलिका 1

प्रतिदर्श का जनसांख्किीय विवरण

विवरण	संख्या	प्रतिशत
कुमाऊँ	270	46.55
गढ़वाल	310	53.45
योग	580	100
पुरुष	348	60
महिला	232	40
योग	580	100
परिवार सहित पलायन	224	38.62
अकेले पलायन	356	61.38
योग	580	100
थ्ववाहित	322	55.52
टविवाहित	258	44.48
योग	580	100
30 वर्ष तक	284	48.97
30 वर्ष से 60 वर्ष तक	224	38.62
60 वर्ष से अधिक	72	12.41
योग	580	100
हाईस्कूल	52	8.97
इंटरमीडिएट	156	26.90
स्नातक	212	36.55
स्नातकोतर	160	27.59
योग	580	100
थ्कसान	46	7.93
बेरोजगार	198	34.14
व्यापार	76	13.10
छात्र	78	13.45
सेवारत	172	29.66
सेवानिवृत	10	1.72
योग	580	100

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.102

तलिका 1 में 580 उत्तरदाताओं का सामाजिक जनसांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें से 270 (46.55%) उत्तरदाता कुमाऊँ मण्डल से तथा 310 (53.45%) उत्तरदाता गढ़वाल मण्डल से संबंधित हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों मण्डलों का प्रतिनिधित्व संतुलित है। लैंगिक आधार पर 348 (60%) उत्तरदाता पुरुष तथा 232 (40%) महिलाएँ हैं, जो दर्शाता है कि पलायन की प्रक्रिया में पुरुषों की भागीदारी अपेक्षा त अधिक है। पलायन के स्वरूप के आधार पर 224 (38.62%) उत्तरदाताओं ने परिवार सहित पलायन किया, जबकि 356 (61.38%) ने एकल पलायन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एकल पलायन की प्रवृत्ति अधिक प्रचलित है। वैवाहिक स्थिति के अनुसार 322 (55.52%) उत्तरदाता विवाहित तथा 258 (44.48%) अविवाहित हैं। आयु वर्ग के अनुसार 284 (48. 97%) उत्तरदाता 30 वर्ष तक के हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि युवा वर्ग पलायन में अग्रणी है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर सर्वाधिक 212 (36.55%) उत्तरदाता स्नातक तथा 160 (27.59%) स्नातकोत्तर हैं, जो यह दर्शाता है कि शिक्षित वर्ग भी रोजगार एवं सामाजिक उन्नयन हेतु पलायन कर रहा है। व्यवसाय के आधार पर सर्वाधिक 198 (34.14%) उत्तरदाता बेरोजगार थे, जबकि 172 (29.66%) सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी पलायन का एक प्रमुख कारक है। समग्र रूप से तालिका 1 यह संकेत करती है कि उत्तराखण्ड में पलायन मुख्यतः युवा, शिक्षित एवं रोजगार की तलाश में रहने वाले वर्ग में अधिक पाया जाता है।

तालिका 2

पलायन के कारण परिवार सहित व एकल पलायन करने वाले निवासियों के अनुसार सामाजिक स्तर पर प्रभाव का विवरण (प्रतिषत में)

विवरण	परिवार सहित पलायन (%)	एकल पलायन (%)
पलायन के कारण आपके रहन सहन के स्तर में परिवर्तन हुआ	69.82	71.46
पलायन के कारण आपकी सामाजिक सुरक्षा प्रभावित हुई	68.21	64.72
पलायन के कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई	70.00	71.80
पलायन के कारण आपका खान पान का स्तर रहता ळे	66.07	64.04
पलायन के कारण आपका आवास स्थल प्रभावित हुआ	65.36	65.62
पलायन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति प्रभावित हुई	71.61	70.00
पलायन के कारण आपको मिलने वाली परिवहन सुविधा प्रभावित हुई	68.39	70.11
पलायन का कारण स्व संतुष्टि प्रभावित हुई	64.11	65.06
पलायन के कारण आपको प्रा तिक आपदाओं से सुरक्षा प्रभावित हुई	68.75	69.66
पलायन के कारण आपको जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रभावित हुई	67.14	64.94
औसत	67.95	67.74

स्रोत : प्राथमिक आकड़ों पर आधारित

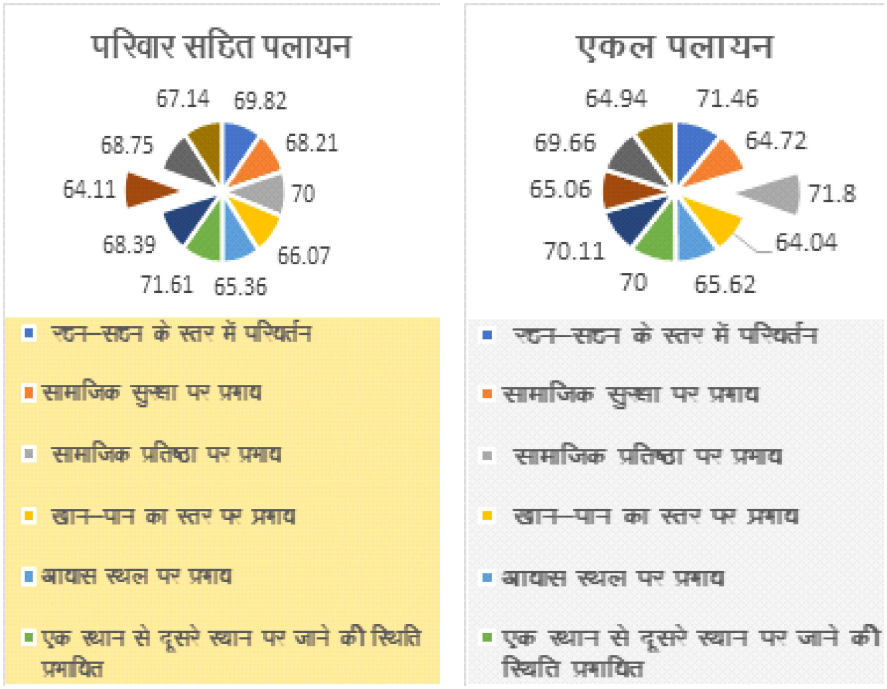

तलिका 2 में परिवार सहित तथा एकल पलायन करने वाले निवासियों के सामाजिक स्तर पर पलायन के प्रभाव का प्रतिषत के रूप में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। दोनों समूहों में पलायन के पश्चात् सामाजिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। रहन सहन के स्तर में परिवर्तन परिवार सहित पलायनकर्ताओं में 69.82% तथा एकल पलायनकर्ताओं में 71.46% पाया गया, जो दर्शाता है कि जीवन स्तर में सुधार दोनों समूहों में लगभग समान है। सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार परिवार सहित पलायनकर्ताओं में 70% तथा एकल पलायनकर्ताओं में 71.80% दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि एकल पलायनकर्ताओं में सामाजिक पहचान एवं प्रतिष्ठा में अपेक्षा त थोड़ा अधिक सुधार अनुभव किया गया। परिवहन सुविधा एवं स्थान परिवर्तन की स्थिति में परिवार सहित पलायनकर्ताओं में 71.61% तथा 68.39% सकारात्मक प्रभाव पाया गया, जो यह संकेत करता है कि परिवार सहित पलायन करने पर आवागमन एवं सुविधा की दृष्टि से अपेक्षा त अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। प्राकृतिक आपदाओं एवं वन्यजीवों से सुरक्षा के संदर्भ में दोनों समूहों में लगभग समान सकारात्मक प्रतिक्रिया (लगभग 68 69%) दर्ज की गई। दोनों समूहों का औसत (परिवार सहित 67. 95%, एकल 67.74%) लगभग समान पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तर पर पलायन का प्रभाव दोनों प्रकार के पलायनकर्ताओं पर लगभग समान रूप से सकारात्मक है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.102

परिवार सहित व एकल पलायन करने वाले निवासियों के मध्य पलायन के कारण सामाजिक स्तर में सम्बंध का विवरण

ANOVA (One Way) परीक्षण का प्रयोग किया गया है

Anova: Single Factor						
SUMMARY						
Groups	*Count*	*Sum*	*Average*	*Variance*		
Column 1	10	679.4643	67.94643	5.295139		
Column 2	10	677.4157	67.74157	9.671759		
ANOVA						
Source of Variation	*SS*	*Df*	*MS*	*F*	*P-value*	*F crit*
Between Groups	0.209829	1	0.209829	0.028039	0.868884	4.413873
Within Groups	134.7021	18	7.483449			
Total	134.9119	19				

एक कारक ANOVA के परिणाम यह दर्शाते हैं कि अध्ययन में शामिल दोनों समूहों के औसत मानों में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। कॉलम 1 का औसत मान 67.95 है, जबकि कॉलम 2 का औसत मान 67.74 है, जो दोनों समूहों के बीच बहुत ही नगण्य अंतर को दर्शाते है। गणना किया गया F–मान 0.028 है, जो कि क्रिटिकल F–मान 4.414 से काफी कम है, तथा इसका p–मान 0.869 है, जो 0.05 के स्तर से कही अधिक है। यह स्पष्ट करता है कि दोनों समूहों के बीच पाया गया अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं है और यह केवल यादृच्छिक परिवर्तन के कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, समूहों के भीतर विचरण (7.48) समूहों के बीच विचरण (0. 21) की तुलना में काफी अधिक है, जो इस निष्कर्ष को और मजबूत करता है कि दोनों समूह सांख्यिकीय रूप से समान हैं। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। अध्ययन में कुल 580 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया, जिनमें से 61.38 प्रतिशत उत्तरदाता एकल रूप से तथा 38.62 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार सहित पलायन करने वाले पाए गए। यह तथ्य दर्शाता है कि रोजगार, शिक्षा एवं बेहतर जीवन–स्तर की खोज में एकल पलायन की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक है। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों ही समूहों में पलायन के पश्चात् सामाजिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए गए। विशेष रूप से रहन–सहन के स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आवागमन सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया, जिससे उत्तरदाताओं के सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। परिवार सहित पलायन करने वाले उत्तरदाताओं में परिवहन सुविधाओं, आवासीय स्थिति तथा स्थान परिवर्तन से संबंधित परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक प्रभाव पाया गया। इसका प्रमुख कारण यह है कि परिवार के साथ

पलायन करने पर स्थायित्व एवं सामाजिक सुरक्षा की भावना अधिक सुदृढ़ होती है। दूसरी ओर एकल पलायन करने वाले उत्तरदाताओं में सामाजिक प्रतिष्ठा तथा व्यक्तिगत जीवन–स्तर में अपेक्षाकृत अधिक सुधार देखा गया जो उनके व्यक्तिगत आर्थिक अवसरों एवं स्वतंत्र निर्णय क्षमता से संबंधित है। अध्ययन में एनोवा परीक्षण के माध्यम से यह भी प्रमाणित हुआ कि परिवार सहित पलायनकर्ताओं एवं एकल पलायनकर्ताओं के मध्य सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पलायन का सामाजिक प्रभाव दोनों ही समूहों पर लगभग समान रूप से सकारात्मक है। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन मुख्यतः जीवन–स्तर में सुधार की आकांक्षा से प्रेरित है तथा यह सामाजिक दृष्टि से दोनो ंप्रकार के पलायनकर्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है।

सुझाव

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन मुख्यतः बेहतर जीवन–स्तर की आकांक्षा से प्रेरित है। अतः सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क परविहन, स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ और संतुलित विकास किया जाना आवश्यक है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या को शहरी क्षेत्रों के समान मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। इसके साथ–साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु कृषि आधारित उद्योगों, कुटीर एवं लघु उद्योगों, स्वरोजगार योजनाओं तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि विशेष रूप से युवाओं को अपने मूल निवास स्थान पर ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। अध्ययन में यह भी पाया गया कि परिवहन एवं संचारा व्यवस्था सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः सड़क संपर्क, सार्वजनिक परिवहन तथा डिजिटल कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों के बढ़ते खतरे तथा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हेतु प्रभावी नीतियाँ एवं संरचनात्मक व्यवस्थाएँ विकसित की जानी चाहिए, जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित एवं स्थिर बन सके। अंततः ग्रामीण सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, सामाजिक सहभागिता तथा स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि इन सभी पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाए, तो अनावश्यक एवं मजबूरीवश होने वाले पलायन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

सन्दर्भ

1. Ali Basarat Md (2020). Study on Labor migration in Apparel industry, American Journal of Engineering (AJER), Volume-9, pp-83-88
2. Arya, N., Jindal, M. (2020). Human migration, digital flowers market and banking services of Uttarakhand. International Research Journal of Commerce, Arts and Science, 11(12), 23–27. ISSN: 2319-9202.

3. Choudhury Sayantani Roy and Ms. Joarder Suranjana. (2020). Reverse Migration Due to Long Lockdown in India- Is it Sustainable?, International Journal of Engineering and Management Research, vol. 10, pp. 139-144
4. Doliñska A, Joñczy R, Poskart Rokita D. (2020). Post-Secondary-School Migration of Young People to Large Regional Centres as a Factor of Depopulation and Disharmonious Regional Development in Poland, European Research Research Studies Journal Volume XXIII, pp. 260-279
5. Garg, V., Jindal, M. (2021). An analytical study of production and storage capacity of sugar mills in Bulandshahr district of Uttar Pradesh. Research Journal of Philosophy and Social Sciences, XLVI(2), 316–323. ISSN: 0258-1701.
6. Goswami, D., Jindal, M. (2021). Awareness of farmers about the primary agriculture credit societies: With special reference to Uttar Pradesh and Uttarakhand. International Journal of Engineering and Management Research, 11(3), 209–212. ISSN: 2250-0758.
7. Jindal, M. (2020). Customer satisfaction of Nainital District Co-operative Bank. Shodh Sanchar Bulletin, 10(39), 160–167. ISSN: 2229-3620.
8. Jindal, M. (2021). Services of co-operative banks of Uttarakhand. ShodhSarita, 8(29), 190–194. ISSN: 2348-2397.
9. Jindal, M. (2024). Agile management system with financial technology. International Journal of Agile Systems and Management, 17(3), 396–419.
10. Jindal, M., Sharma, V. L. (2020). Usability of online banking in India during COVID-19 pandemic. International Journal of Engineering and Management Research, 10(6), 69–72. ISSN: 2250-0758.
11. Jindal, M., Srivastava, S. (2021). Customer satisfaction of Almora Urban Co-operative Bank. Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal (Special Issue), 2620–2625. ISSN: 2319-4979.
12. Joshi, C. S., Jindal, M. (2022). Service quality of rural co-operative sector banks in India. Shodhasamhita, Issue IX, No. II (II), 135–150. ISSN: 2277-7067.
13. Nettikallappa Kummara, Dr Naik.K.Krishna (2020). IMPACT OF MIGRATION ON SOCIO- ECONOMIC CONDITIONS OF SCHEDULED TRIBE WOMEN IN ANANTAPURAMU DISTRICT: AN EMPIRICAL EVIDENCE, International Journal of Multidisciplinary Research Review, Vol.6.

14. Saxena, S., Jindal, M. (2019). Customer satisfaction on banking services in Indian growing economy: Nainital district. International Journal of Engineering and Management Research, 9(4), 74–77. ISSN: 2250-0758.
15. Saxena, S., Jindal, M. (2021). Service quality of government banks in rural areas of Uttarakhand. International Journal of Engineering and Management Research, 11(5), 169–174. ISSN: 2250-0758.
16. Sharma, V. L., Jindal, M. (2022). Financial ratio analysis of co-operative banks in Uttarakhand. Journal of Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University, IX(II), 969–980. ISSN: 2277-7067.
17. Sharma, V. L., Jindal, M., Bajpai, M. (2022). Financial statement analysis of co-operative bank in Uttarakhand. Research Journal of Philosophy and Social Sciences, XLVII(1), 129–136. ISSN: 0258-1701.
18. Singh, N. K., Jindal, M. (2025). Financial statement analysis of Uttarakhand State Co-operative Bank. Swami Vivekanand Advanced Journal for Research and Studies, 2(2), 47–54.
19. Singh, N. K., Jindal, M. (2025). भारत के शीर्ष 10 गाँवों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन Anusandhan Vatika, 15(3), 152-157.